भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3158

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

तुरतुक हनु रोड

†3158. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में तुरतुक हनु सड़क के निर्माण की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त सड़क के निर्माण की धीमी गति की जानकारी है;

(ग) क्या देरी के कारणों को चिह्नित किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त सड़क के निर्माण में तेजी लाने और उसे पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, क्योंकि यह स्थानीय लोगों और सैन्यकर्मियों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती हैं।

संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख की हनुथांग को तुरतुक से जोड़ने वाली सड़क जिसकी लंबाई लगभग 77.35 किलोमीटर है, जिसमें से पैकेज-1 (किमी 0.00 से किमी 4.031) और पैकेज-III (किमी 72.35 से किमी 77.00) क्रमशः संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के विशेष विकास पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः 13.78 करोड़ रुपये और 45.87 करोड़ रुपये है का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

पैकेज-II के अंतर्गत 68.32 किलोमीटर लंबाई की परियोजना को सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत मई 2025 में 229.52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया है।

सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 की धारा 7ए और 11 के आधार पर, सरकार ने सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए धन आवंटन हेतु मानदंडों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमति दिए जाने तक, पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्य पूरा होने की अवधि 36 महीने से अधिक नहीं होगी और अन्य राज्यों के लिए 24 महीने से अधिक नहीं होगी।

*****